डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 16 दिसम्बर, 2025, डिस्पेच दिनांक 16 दिसम्बर, 2025

| वर्ष 69 | अंक 14 | भोपाल | 16 दिसम्बर, 2025 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सहकारी संस्थाएं किसानों को सशक्त बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा

सहकारी समितियों का प्राथमिकता से किया जाए कंप्यूटराईजेशन

पंचायत स्तर पर पैक्स स्थापित किए जाएं

पैक्स के डिफॉल्टर किसानों को लाया जाएगा मुख्य धारा में

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना सहकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है। आगामी वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अतः किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने और फसल चक्र के अनुसार उन्हें सुगमता से सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग कृषि विपणन सहकारी समितियां को मजबूत बनाने बनाने पर विशेष ध्यान दे। सहकारी समितियों का प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटराईजेशन किया जाए, ताकि किसानों को सुगमता और पारदर्शिता के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिति के पदाधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष संपत्ति का वार्षिक विवरण आवश्यक रूप से देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पंचायत स्तर पर पैक्स स्थापित किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग ने अपेक्स बैंक की 4 करोड़ 27 लाख 4 हजार 190 रुपए अंश पूंजी का लाभांश चेक भेंट किया। बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता इस अवसर पर उपस्थित थे।

बैठक में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण, खाद और बीज वितरण, कृषि उपज के समर्थन मूल्य पर उपार्जन, उचित मूल्य दुकानों के संचालन और सहकार से समृद्धि के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के तहत पिछले 2 वर्ष में प्राप्त उपलब्धियों, नवाचारों का प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में आगामी 3 वर्ष की कार्य योजना पर भी विचार विमर्श हुआ।

विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियाँ

- 15 कमजोर जिला सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रत्येक जिला बैंक को 50-50 लाख रूपए की अंशपूंजी शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई।
- मध्यप्रदेश एम-पैक्स के कम्प्यूटराईजेशन और ऑनलाईन ऑडिट में देश में सबसे आगे है।
- कृषकों को उनके खातों के संबंध में जानकारी एस.एम.एस. से उपलब्ध कराई जा रही है।
- पैक्स के सोसायटी मैनेजर के लिए कैडर व्यवस्था लागू।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों के मापदंड के अनुरूप सहकारी बैंकों में प्रबंधकों और बैंकिंग सहायकों की भर्ती तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- पैक्स से बहुउद्देशीय गतिविधियों का संचालन आरंभ।
- कुल 4460 कॉमन सर्विस सेंटर, 4518 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र, 63 जन औषधि केन्द्र, 59 जल कर वसूली केन्द्र, दो एग्री ड्रोन और 25 इफ्को आउटलेट की व्यवस्था।
- अब तक पैक्स को 4060 तथा डेयरी समिति को एक माइक्रो एटीएम वितरित।
- सहकारी कानूनों में जनसामान्य की सुविधा की दृष्टि से संशोधन किए गए हैं।
- सहकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सहकारी समितियों को व्यवसाय के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025: नाबार्ड, म.प्र. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सहकारिता सम्मेलन का आयोजन

मार्च 2026 तक सभी पैक्स को ई-पैक्स में परिवर्तित करेंगे- मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग

भोपाल : सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग के मुख्य आतिथ्य में सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में नाबार्ड, मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सहकारिता पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। मंत्री श्री सारंग ने सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को सम्मानित किया। सम्मेलन में सहकारिता आयुक्त श्री मनोज पुष्प, नाबार्ड मध्यप्रदेश की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सी. सरस्वती, एमडी अपेक्स बैंक श्री मनोज गुप्ता, उप सचिव सहकारिता श्री मनोज सिन्हा सहित सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिला सहकारी बैंक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक एवं पैक्स समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है सहकारिता

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश मिशन कर्मयोगी में निभा रहा देश में अग्रणी भूमिका

विभाग को सफल व प्रभावी क्रियान्वयन पर मिली सराहना

सहकारिता आंदोलन को मजबूत करेगा राष्ट्रीय कर्मयोगी मिशन : मंत्री श्री सारंग

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंत्रालय में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के एचआर विशेषज्ञ डॉ. आर. बाला सुब्रमण्यम (बालू) तथा सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में विभाग में मिशन कर्मयोगी के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल मिशन कर्मयोगी के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मध्यप्रदेश का सहकारिता विभाग अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी से विभागीय कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी पहल मील का पत्थर साबित होगी।

विभाग को प्रभावी क्रियान्वयन पर मिली सराहना

मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के एचआर विशेषज्ञ डॉ. आर. बाला सुब्रमण्यम (बालू) ने मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सबसे अधिक और प्रभावी कार्य मध्यप्रदेश द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के सफल मॉड्यूल को अन्य राज्यों में भी लागू करेंगे।

मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम में विभागीय उपलब्धियाँ

सहकारिता विभाग ने अपने सभी 1122 अधिकारियों और कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड कर लिया है। विभागीय कर्मचारियों ने 11337 से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं, जो सीखने की संस्कृति और सतत कौशल विकास के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता दर्शाता है। इन प्रशिक्षणों से विभागीय कार्यक्षमता, सेवा वितरण और प्रशासनिक गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल मिशन कर्मयोगी

मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को आधुनिक, तकनीक-सक्षम और भविष्य उन्मुख प्रशासनिक क्षमताओं से लैस करना, शासन प्रणाली को कुशल, पारदर्शी और जन-केन्द्रित बनाना, प्रशिक्षण के माध्यम से निरंतर सीखने की संस्कृति विकसित करना है। कर्मयोगी पोर्टल इसी उद्देश्य की पूर्ति का प्रमुख माध्यम है, जिसके द्वारा कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित आवश्यक कौशल और ज्ञान को निरंतर अपडेट कर सकते हैं।

NCCT ने सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिए एक लिखित उत्तर में बताया कि देश में सहकारी शिक्षा और क्षमता-विकास को नई दिशा देने के लिएनेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग (NCCT)लगातार महत्वपूर्ण पहलें कर रहा है।

शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के निर्देश पर NCCT ने कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) आधारित सहकारी शिक्षा मॉड्यूल तैयार करने हेतु एक समिति बनाई है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को स्कूली स्तर से ही सहकारिता आंदोलन के सिद्धांतों और लाभों से परिचित कराना है।

उन्होंने बताया किNCERT ने कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक में सहकारिता पर एक नया अध्याय शामिल किया है, जो मंत्रालय के मार्गदर्शन और NCCT की पहल का परिणाम है। इसके साथ ही NCERT और NCCT ने मिलकर सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष "सहकारिता मॉड्यूल" भी विकसित किया है, ताकि युवाओं को सहकारिता की भूमिका और करियर संभावनाओं की जानकारी मिल सके।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने NCCT के लिए"Grants-in-Aid General"नाम से नया वित्तीय प्रावधान शुरू किया है, जिससे इसके प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी और Training and Development Fund पर निर्भरता कम होगी। साथ ही, NCCT के हर संस्थान में प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भवन उप-समितियाँभी गठित की गई हैं।

प्रशिक्षण गतिविधियों में तेजी का उल्लेख करते हुए शाह ने बताया कि CSC e-Governance Services India Ltd के साथ मिलकर NCCT ने PACS के लिए 648 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें25 राज्यों के 564 जिलों के 30,210 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

इसके अलावा, 24,500 से अधिक PACS के लिए एक नई ऑन-बोर्डिंग और सक्रियण प्रशिक्षण श्रृंखला भी शुरू की गई है।

देशभर में नई गठित22,283 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (M-PACS) के लिए भी NCCT प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। अब तक153 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजितकर6,817 प्रतिभागियोंको प्रशिक्षित किया गया है (31 अक्टूबर 2025 तक)। शाह ने बताया कि कृषि मंत्रालय के फसल बीमा प्रभाग के साथ हुए एक समझौते के तहत NCCT 10,000 PACS हितधारकोंके लिए200 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिससे PMFBY और RWBCIS योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

शैक्षणिक क्षेत्र में भी NCCT सक्रिय है। RICM चंडीगढ़ ने सहकारिता पर आधारित द्विवार्षिक शोध पत्रिका "सहकारिता अनुसंधान"शुरू की है, जिसका पहला अंक अप्रैल 2025 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा संस्थान अपनेAICTE अनुमोदित PGDM-ABM कार्यक्रम को भी पुनः प्रारंभ कर रहा है, जिसकी प्रवेश प्रक्रिया दिसंबर 2025 से शुरू होगी।

एक नई पहल के रूप में PMBI और NCCT मिलकर PACS को प्रशिक्षण देंगे, जिससे देश में 300 नए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJKs) को स्वीकृत स्टोर कोडों के साथ संचालन में लाया जा सकेगा।

इन सभी पहलों का उल्लेख करते हुए अमित शाह ने कहा कि NCCT देश में सहकारी शिक्षा और संस्थागत क्षमता-विकास को मजबूत करने के सरकार के मिशन का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।

जिला सहकारी बैंकों का विलय कर राज्यस्तरीय बड़ा सहकारी बैंक बनाए

भोपाल। मप्र सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी के जिला सहकारी बैंकों का सुदृढ़ीकरण किया जाए। जिला सहकारी बैंकों का मर्ज कर प्रदेश स्तर पर एक बड़ा सहकारी बैंक बनाने के लिये विधिक और वित्तीय पहलुओं पर विचार करें और अगले 3 साल के लिये लक्ष्य में इसे शामिल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक, सोसायटी में गणन और शार्टेज की स्थिति में अचल संपत्ति कुर्क कर वसूली की कार्यवाही की जाए। सोसायटी के कर्मचारियों और पदाधिकारियों की अचल संपत्ति का विवरण हर साल अनिवार्य रूप से लिया जाए। वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सहकारिता विभाग कृषि विपणन सहकारी समितियों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दे। सहकारी समितियों का प्राथमिकता के आधार पर कम्प्यूटरीकरण करें, ताकि किसानों को परेशानी नहीं हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पंचायत स्तर पर पैक्स बनाएं।

3 साल में ये करने का लक्ष्य दिया- पैक्स के डिफॉल्टर किसानों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। जिला बैंक बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आवश्यक अनुमति लेकर ग्राहकों को क्यूआर कोड दिया जाए। जिला बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा। सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास के लिए ईको सिस्टम बने।

एनखी सेवाओं ली जाए, बॉन्ड वाले डॉक्टर्स को शासकीय डॉक्टर्स के रूप में भर्ती करने के लिए, इनके भर्ती नियम संशोधित किए जा रहे हैं। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। बॉन्ड वाले 2500 डॉक्टर्स जल्द ही सरकारी सेवा में आएंगे।

पत्रा मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन के लिए नड्डा को किया आमंत्रित : म.प्र. में प्रस्तावित कटनी, पन्ना, बैतूल और धार में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और भूमिपूजन कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को आमंत्रण दिया। विभागीय समीक्षाओं के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली रवाना हुए, इस दौरान उन्होंने भूमिपूजन के लिए नड्डा को आमंत्रित किया।

सहकारिता मंत्रालय ने अमृत काल में शुरू किए चार राष्ट्रीय अध्ययन : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया कि सहकारिता मंत्रालय ने अमृत काल के दौरान सहकारी क्षेत्र में व्यापक सुधारों को आगे बढ़ाने और भविष्य उन्मुख आधुनिक सहकारी व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से चार बड़े राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन शुरू किए हैं।मंत्री शाह ने बताया कि नेशनल लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन (NLCF) पर विस्तृत अध्ययन AFC इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरा किया जा चुका है। इस रिपोर्ट में NLCF को एक व्यवसाय-उन्मुख महासंघ में बदलने का रोड मैप प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बुनियादी ढाँचे का उन्नयन, सेवाओं का विस्तार और प्रशिक्षण प्रणाली की मजबूती जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।

उन्होंने आगे बताया किनेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (NCUI)के लिए 2022 से 2047 तक की अवधि को कवर करते हुए एक दीर्घकालिक सामरिक अध्ययन जारी है। इसे भी AFC इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य MSCS अधिनियम की धारा 24 का अनुपालन सुनिश्चित करना, सहकारी शिक्षा को आधुनिक रूप देना, सुशासन को मजबूत करना, गतिविधियों का विस्तार और आगामी 25 वर्षों के लिए NCUI की राष्ट्रीय भूमिका का स्पष्ट विज़न तैयार करना है।

मछली पालन क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय सहकारी समिति FISHCOP FEDकी वृद्धि को गति देने के लिए भी एक व्यापक राष्ट्रीय अध्ययन शुरू किया गया है। इस अध्ययन के तहत अमृत काल में 25 प्रतिशत व्यवसाय वृद्धि, विविधीकरण, डिजिटल समाधान और सुशासन सुधार का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही छह राज्यों की मत्स्य सहकारिताओं को विशेष रूप से मजबूत करने की योजना है।अंत में, मंत्री शाह ने बताया किLINAC (Laxmanrao Inamdar National Academy for Cooperative Research & Development)द्वारा एकइम्पैक्ट असेसमेंट अध्ययनभी पूरा किया गया है। इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में चल रही पहलों का मूल्यांकन करना और पूरे क्षेत्र को अधिक सक्षम, प्रभावी तथा लचीला बनाना है।

मोदी जी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन के अनुरुप डेयरी सहकारिता आज किसानों के कल्याण की सक्षम शक्ति

दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के वाव-थराद जिले में स्थित बनास डेयरी में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और मुरलीधर मोहोल, समिति के सदस्य सांसदगण, सहकारिता सचिव डॉ आशीष भूटानी सहित सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में भारत की डेयरी सहकारिता क्षेत्र और श्वेत क्रांति 2.0 को लेकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में संसदीय परामर्शदात्री समिति के समक्ष सहकारी डेयरी क्षेत्र पर एक व्यापक प्रस्तुति दी गई, जिसमें डेयरी क्षेत्र की संभावनाओं तथा इस क्षेत्र में सर्कुलैरिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने में सहकारी डेयरी समितियों की भूमिका को उजागर किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की आय वृद्धि, महिला सशक्तिकरण और देश की दुग्ध आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सहकार से समृद्धि' के विज़न के अनुरूप डेयरी सहकारिता आज किसानों के विकास की सक्षम शक्ति बन चुकी है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत में हर महिला की आय बढ़ाने और हर घर को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम डेयरी सहकारिता है। उन्होंने सहकारिता तंत्र को और सशक्त करने हेतु कई नए सुझाव और दिशा-निर्देश भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तरीय मंडलियों को इंश्योरेंस कोऑपरेटिव्स से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण समुदाय को बीमा सेवाओं तक सरल पहुँच मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि डेयरी सहकारी समितियों को इंश्योरेंस के साथ जोड़ा जायेगा, जिससे गाँव के लोगों को दोपहिया और चारपहिया वाहनों का बीमा सहकारिता के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा। श्री शाह ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को अन्य सहकारी संस्थानों में भी निवेश करना चाहिए, ताकि सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर मजबूती और पूँजी का विस्तार हो सके।

श्री अमित शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीन मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं। इनके माध्यम से NDDB और भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जो श्वेत क्रांति 2.0 शुरू की है, उसका उद्देश्य है कि हर पंचायत में एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी बने और पर्याप्त दूध उत्पादन होने पर हर जिले में एक डेयरी स्थापित हो। श्री शाह ने कहा कि यह एक लॉग टर्म कार्यक्रम है, आणंद में स्थापित त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी (TSU) दुग्ध प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ साझेदारी कर बी.एससी और एम.एससी स्तर पर डेयरी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन का पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगी। इन विषयों के ग्रैजुएट अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद देश भर के जिलों में बनास डेयरी के मॉडल को लागू करने में अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि किसान को उसके दूध का पूरा लाभ मिले, इसके लिए इस प्रयास को अवश्य सफल बनाना होगा।

सहकारिता मंत्री ने बनास डेयरी के उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि देशभर के प्रत्येक जिले में चार अत्याधुनिक सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएँगी, ताकि किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन मिल सके। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसलिए किसानों को यह समझाना आवश्यक है कि कब, कौन-सा खाद—यूरिया, डीएपी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स—का उपयोग करना उपयुक्त है, ताकि मिट्टी स्वस्थ रहे और फसल उत्पादकता बढ़े।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के वाव-थराद जिले में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की

श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य हर पंचायत में एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाना और हर जिले में एक डेयरी की स्थापना

डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीन मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गईं

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के ग्रैजुएट देश भर में बनास डेयरी के मॉडल को लागू करने में योगदान देंगे

इंश्योरेंस कोऑपरेटिव्स से गाँवों तक बीमा सेवाओं की सरल पहुँच सुनिश्चित होगी

प्रत्येक जिले में चार अत्याधुनिक सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित होंगी, ताकि किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन हो

50 दिवसीय फ़ैशन डिज़ाइनिंग एवं कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल एवं विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 50 दिवसीय फ़ैशन डिज़ाइनिंग एवं कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्र परिसर में किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र के प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ की गई। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में डिज़ाइनिंग तथा कढ़ाई जैसे कौशल ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं और युवाओं के लिए एक सशक्त रोजगार माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को 50 दिवसीय प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाने तथा स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया।

शुभारंभ कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित फ़ैशन डिज़ाइनर सुश्री अर्चना सिंह ने फैशन एवं परिधान उद्योग में कौशल विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के विशेषज्ञ प्रशिक्षण से प्रतिभागी न केवल डिज़ाइनिंग तकनीकों में दक्ष होंगे, बल्कि भविष्य में स्वयं का उद्यम भी स्थापित कर सकते हैं।

इसी क्रम में मास्टर ट्रेनर श्रीमती हूमा ख़ान ने प्रशिक्षण की संरचना, व्यवहारिक अभ्यास एवं आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में हाथ कढ़ाई, मशीन कढ़ाई, परिधान डिज़ाइन, रंग संयोजन, कटिंग-पैटर्न मेकिंग आदि प्रमुख विषय शामिल होंगे।

कार्यक्रम में केन्द्र के प्रशिक्षक श्री बाबूलाल कुशवाहा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रतिभागियों का स्वागत किया और प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन एवं नियमित उपस्थिति के महत्व पर जोर दिया।

समूचे कार्यक्रम का सफल संचालन केंद्र के प्रशिक्षक श्री हृदेश कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय युवाओं एवं महिलाओं के कौशल उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा भविष्य में उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा।

गुजरात के वाव-थराद जिले में बनास डेयरी द्वारा नवनिर्मित बायो सीएनजी और फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन एवं 150 टन के पावडर प्लांट का शिलान्यास किया - शाह

दिल्ली, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के वाव-थराद जिले में बनास डेयरी द्वारा नवनिर्मित बायो सीएनजी और फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन एवं 150 टन के पावडर प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकर चौधरी, केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और श्री मुरलीधर मोहोल, केन्द्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि बनासकांठा में बनास डेयरी की शुरुआत करने वाले गलबाभाई नानजीभाई पटेल ने जो यात्रा शुरू की थी, वह धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते इस मुकाम पर पहुँच गई है कि आज यहाँ 24 हजार करोड़ रुपए तक का कारोबार हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह देश भर में जहाँ भी जाते हैं, वहाँ गर्व से कहते हैं कि गुजरात के गाँवों को समृद्ध बनाने का काम गुजरात की माताओं-बहनों ने किया है। यहाँ के किसान भाइयों, विशेष रूप से सहकारी आंदोलन के अगुआ लोगों, गाँव की दूध मंडलियों के चेयरमैन और बनास डेयरी के डायरेक्टर्स को शायद पता भी न हो कि उन्होंने कितना बड़ा चमत्कार कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि 24 हजार करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी करना बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए भी पसीना छुड़ाने वाला काम होता है, लेकिन बनासकांठा की बहनों और किसानों ने देखते-ही-देखते 24 हजार करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज वह अपने साथ देश की संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—के सांसदों को लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी जनवरी में पूरे देश की सभी डेयरियों के लगभग 250 चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनासकांठा के सहकारी डेयरी क्षेत्र में हुए चमत्कार को अपनी आँखों से देखने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1985-87 के अकाल के बाद जब वह इस इलाके में आते थे और किसानों से पूछते थे तो बताया जाता था कि वह पूरे साल में सिर्फ एक फसल उगा पाते हैं, लेकिन अब बनासकांठा का किसान एक साल में तीन-तीन फसल उगाता है। मूंगफली भी उगाता है, आलू भी उगाता है, गर्मियों में बाजरा भी बोता है और खरीफ की फसल भी लेता है, जबकि पच्चीस साल पहले बनासकांठा में तीन फसल की खेती करना एक स्वप्न मात्र था।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गुजरात के उन इलाकों से यहाँ पानी की उपलब्धता कराने का काम किया, जहां पानी प्रचुर मात्र में उपलब्ध था। उन्होंने कहा कि सुजलाम-सुफलाम योजना के तहत नर्मदा और माही नदी का अतिरिक्त पानी बनासकांठा पहुँचा। पहले यहाँ का किसान दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। आज उसी किसान ने अपनी जमीन को स्वर्ग बना दिया और पूरे बनासकांठा को समृद्ध बना दिया।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमारी यह परंपरा या आदत नहीं रही कि कोई बड़ा काम करने पर उसका पूरा दस्तावेजीकरण किया जाए या उसका इतिहास लिखा जाए। लेकिन उन्होंने दो विश्वविद्यविद्यालयों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे बनासकांठा और मेहसाणा में जल-संचय तथा पानी के माध्यम से आई समृद्धि और लोगों के जीवन में आए परिवर्तन पर विस्तृत रिसर्च करें। उन्होंने कहा कि बनासकांठा का यह परिश्रम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और पूरे देश के ग्रामीण विकास के इतिहास में एक प्रेरणास्त्रोत बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि खुशी की बात यह है कि इस परिश्रम में महिलाओं का बड़ा योगदान है। श्री शाह ने कहा कि 24 हजार करोड़ रुपए के इस विशाल कारोबार में दूध इकट्ठा करने की सारी मेहनत बनासकांठा की बहनों, बेटियों और माताओं के हाथों से हुई है। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाली विश्व की तमाम एनजीओ के सामने सबसे जीवंत और सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था खड़ी हो चुकी है कि बिना किसी आंदोलन या बिना किसी नारे के, सीधे माताओं-बहनों के बैंक खाते में हर हफ्ते उनके दूध का पूरा पैसा पहुँच रहा है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि बनास डेयरी आज एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक डेयरी बन चुकी है। इसमें गलवा काका का बड़ा योगदान है। गलबा काका ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके हृदय में केवल किसान हित की भावना बसती थी। वर्ष 1960 में वडगाम और पालनपुर – सिर्फ दो तहसीलों के मात्र आठ गाँवों की दूध मंडलियों से शुरू हुई यह यात्रा आज 24 हजार करोड़ रुपए के टर्नओवर तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि गलबाभाई द्वारा शुरू की गई परंपरा का मूल मंत्र बहुत सरल था कि "हमारे पास रुपये तो कम हैं, लेकिन हम खूब सारे लोग हैं।" श्री शाह ने कहा कि बहुत सारे लोगों द्वारा थोड़े-थोड़े रुपए इकट्ठा करके बड़ा काम करने का उनका विचार एक विशाल वटवृक्ष बन गया है, जो देश ही नहीं, विश्व के सभी सहकारी आंदोलनों को प्रेरणा दे रहा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान इस देश को दिया, उसके बल पर दलित, गरीब, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग भी सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें, ऐसी मजबूत व्यवस्था खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि वह बाबा साहब को हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री शाह ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के तहत गुजरात में चल रही एक विशाल पदयात्रा का समापन समारोह भी आज ही है। उन्होंने कहा कि किसान और सहकारिता का मूल विचार सरदार साहब का ही था। गुजरात ने उसे अपनाया और आज वह विचार एक विशाल वटवृक्ष बन गया है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज यहाँ कई नई शुरुआतें हुई हैं, जिसके तहत बायो सीएनजी प्लांट और मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन और अत्याधुनिक प्रोटीन प्लांट एवं हाई-टेक ऑटोमैटिक पनीर प्लांट का लोकार्पण हुआ। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी ने सर्कुलर इकोनॉमी के जो अभिनव प्रयोग किए हैं, परामर्शदात्री समिति के सदस्य सांसदों को उससे अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक अमूल के नेतृत्व में गुजरात की डेयरियाँ दूध इकट्ठा करती थीं, प्रोडक्ट बनाती थीं, बेचती थीं और जो लाभ होता था, उसे सीधे बहनों और किसानों के बैंक खाते में डाल देती थीं। इस मामले में हम दुनिया में सबसे आगे रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम डेयरी को पूरी तरह सर्कुलर इकोनॉमी बनाएँ। उन्होंने कहा कि गाय-भैंस का एक ग्राम गोबर भी बर्बाद न हो – उससे जैविक खाद बने, बायो-गैस बने, बिजली बने और उससे जो कमाई हो, वह भी वापस किसान के पास आए। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी ने जो बायो CNG प्लांट की परंपरा खड़ी की, वह देश भर की सहकारी समितियों के लिए आदर्श बनेगी। श्री शाह ने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत-से हाई-वैल्यू डेयरी प्रोडक्ट हैं जो अभी भारत में नहीं बन रहे। उन्होंने कहा कि वह आज ही अमूल के चेयरमैन को एक पूरी लिस्ट दे रहे ताकि उन प्रोडक्ट्स के उत्पादन का काम तुरंत शुरू हो। उन्होंने कहा कि इन प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत अधिक मिलती है और विश्व बाजार में इनकी भारी माँग है। अगर हम सिर्फ दही, घी, पनीर बनाने की बजाय इन हाई-वैल्यू प्रोडक्ट्स पर ध्यान देंगे, तो हमारे किसान भाइयों-बहनों को कई गुना अधिक लाभ होगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमें अब डेयरी के साथ-साथ बायोगैस बनाने की शुरुआत करनी है, बायो-सीएनजी बनाने की शुरुआत करनी है। उन्होंने कहा कि अब समग्र भारत की को-ऑपरेटिव डेयरियाँ पशु आहार भी बाजार से नहीं खरीदेंगी। उसे भी को-ऑपरेटिव स्तर पर ही बनाया जाएगा और पशु आहार बनाने से जो लाभ होगा, वह भी सीधे हमारी बहनों के बैंक खाते में पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि इस पूरी व्यवस्था के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए – यह सब भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में तैयार कर दिया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि किसानों के लिए तीन नई राष्ट्रीय को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई हैं – बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए, जैविक उत्पादों की मार्केटिंग के लिए और कृषि निर्यात के लिए। वहीं, डेयरी क्षेत्र के लिए तीन राष्ट्रीय स्तर की को-ऑपरेटिव बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि ये कुल छह को-ऑपरेटिव संस्थाएं मिलकर अब खेती से जुड़ा हर काम करेंगी – चाहे Cheese बनाना हो, प्रोटीन बनाना हो, डेयरी व्हाइटनर, मावा, आइसक्रीम, बेबी फूड बनाना हो; तेल की पैकेजिंग, आटा, शहद, कोल्ड स्टोरेज, आलू चिप्स, बीज उत्पादन या पशु आहार बनाना हो – सारी चीजें डेयरी की इकोनॉमी के अंतर्गत आएंगी और उसका पूरा लाभ पशुपालक के खाते में पहुँचे, यह भारत सरकार का स्पष्ट और मजबूत प्लान है। श्री शाह ने कहा कि वे बनासकांठा के भाइयों-बहनों को भरोसा दिलाते हैं कि पाँच साल के अंदर, सिर्फ दूध के बढ़ते उत्पादन से जो लाभ होगा वह अलग रहेगा, लेकिन आज जितना दूध आता है उसी मात्रा में भी सर्कुलर इकोनॉमी से आपकी आमदनी कम से कम 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाएगी। इसका पूरा डिटेल्ड प्लान तैयार कर लिया गया है और बहुत सौभाग्य की बात है कि इस पूरी डिटेल्ड प्लानिंग का केंद्र बनास डेयरी का हेडक्वार्टर ही बनेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बनासकांठा की तरह पूरे देश के पशुपालकों और किसानों की आमदनी बढ़ाने का यह मॉडल सफल होगा।

ऐतिहासिक अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का समापन

रतलाम। जिला सहकारी संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का समापनसमारोह के मुख्य अतिथि पूर्व गृह एवं सहकारिता मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से प्रदेश को विकसित बनाने के लिये हमने अनेक योजनाएं बनाई। जिससे हर वर्ग को लाभ मिल सके। जब मैं सहकारिता मंत्री था तब हमने 14% ब्याज दर को घटाकर किसानों के लिए 5% कर दिया था, जो घटते घटते आज शून्य प्रतिशत हो गयी है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज पर कृषि ऋण प्राप्त हो रहा है।

श्री कोठारी ने कहा कि सहकारी बैंकों और सहकारी संस्थाओं की बागडोर अधिकारियों के बजाए जन प्रतिनिधियों के हाथों में होना चाहिए। प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाए जाने चाहिए। तभी सहकारी आंदोलन जन जन का आंदोलन बन सकेगा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडेय ने कहा कि एक सबके लिए और सब एक के लिए की अवधारणा पर हम सहकारिता के माध्यम से काम करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। रतलाम जिले में सहकारिता के माध्यम से हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। हमें लिज्जत पापड़ सहकारी संस्था से प्रेरणा लेनी चाहिए जो एक महिला ने शुरू की वह सहकारी संस्था आज 1600 करोड़ का कारोबार कर रही है। डॉ राजेंद्र पांडेय ने कहा कि हम सब मिलकर पूरी कार्ययोजना बनाकर काम करें तो ग्रामीण ही नहीं वरन शहरी क्षेत्र में गली मोहल्ले तक सहकारिता के माध्यम से जनकल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। आज देश के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें राज्य सरकार भी पूरी मदद कर रही है। हमें चाहिए कि उन योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचे तभी सहकारी आंदोलन सार्थक होगा।कार्यक्रम के विशेष अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कहा कि सहकारी सप्ताह के माध्यम से जिले में जागरूकता लाने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2025 के रूप में हम अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहे हैं। इस वर्ष में हमें पूरी ताकत के साथ सहकारी आंदोलन को आगे ले जाने के प्रयास करने चाहिए।

कार्यक्रम के विशेष अतिथि जिला सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी ने आज के विषय "वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए अभिनव सहकारी व्यवसाय मॉडल" पर बोलते हुए कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस क्षेत्र में सहकारिता से अच्छा कोई व्यवसाय मॉडल नहीं हो सकता है। निजी व्यवसाय मॉडल शोषण व आर्थिक असमानता को बढ़ाते हैं। वही सहकारी व्यवसाय मॉडल समानता और समाजवाद के साथ-साथ गुणवत्ता व उचित मूल्य पर काम करता है। अमूल,इफ़को , कृभको जैसे सहकारी बिजनेस मॉडल इसका जीता जागता उदाहरण है।श्री जोशी ने कहा कि सहकारी आंदोलन ने पिछले सात दशकों में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। वर्तमान में प्रदेश का सहकारी आंदोलन बिना जन प्रतिनिधियों के चल रहा है। जिससे नीतिगत निर्णय में विलंब होने से कई काम रूके हुए हैं। लोकतांत्रिक नियंत्रण सहकारिता की आत्मा है। उसे बहाल किया जाना चाहिए।श्री जोशी ने जिला सहकारी संघ द्वारा किए जा रहे प्रचार प्रसार व कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सहित कुछ संस्थाओं से आपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने के बाद भी संघ अच्छा कार्य कर रहा है। उपायुक्त सहकारिता एन.एस. भाटी ने कहा कि जिले में पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया गया है। शासन की मंशानुसार सहकारी संस्थाओं में नवाचार के तहत बहुउद्देशीय बनाया गया है। हमारा प्रयास है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे।

कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए रेडक्रॉस समिति के चेयरमेन प्रितेश गादिया, वाइस चेयरमेन सुशीलमुणत तथा संचालकों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया।विद्युत कर्मचारी सोसाइटी के अध्यक्ष संजय वोरा द्वारा सहकारी संस्थाओं को इनकम टैक्स व जीएसटी में छूट दिया जाने का सुझाव दिया।कार्यक्रम में अतिथियों का पुष्प मालाओं से स्वागत सहकारी नेता संचालक रेडक्रॉस अशोक जैन (लाला), बाबूलाल कर्णधार, पत्रकार गोविंद उपाध्याय, अश्विनी शर्मा ,पंकज परमार, प्रवीण उपाध्याय, निखिलेश शर्मा, प्रथमा कौशिक ,रेखा शर्मा,उषाजैन, सहकार भारती के जिला अध्यक्ष सुनील पोरवाल, सत्यदीप भट्ट पूर्व पार्षद ,वैभव श्री महिला साख संस्था की अध्यक्ष निर्मला राणावत , उपाध्यक्ष आशा उपाध्याय कवि अखिलचंद्र शर्मा, आदित्य मंडवारिया, कमल बुंदेला ,जिला विपणन अधिकारी यश सिंह, के .सी. मोदी ,कमल बुंदेला, भावेश द्वारा किया गया।कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्राचार्य निरंजन कुमार कसारा ने तथा आभार प्रदर्शन जिला सहकारी संघ के जनसंपर्क अधिकारी पिंकेश भट्ट ने किया।

गुजरात में भारत की प्रथम त्रिभुवनदास सहकारी यूनिवर्सिटी

सीहोर, जिला सहकारी संघ मर्यादित सीहोर के तत्वाधान में 72 वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2025 के अन्तर्गत दिनांक 15 नवम्बर 2025 को बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित हकीमाबाद में वरिष्ठ सहकारी नेता माननीय देवीसिंह परमार काकाजी पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं जिला सहकारी संघ सीहोर संचालक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीहोर के मुख्य आतिथ्य तथा रामचन्द्र परमार सरपंच बगड़ावदा, मांगीलाल चौहान सरपंच हकीमाबाद, दिलीप सिंह मेवाड़ा, दयाराम पाटीदार, मनोहर सिंह ठाकुर मोहनसिंह परमार के विशेष आतिथ्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिवर्तन सहकारी शिक्षा विषय पर सम्बोधित करते हुए कहाकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदीजी एवं प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता आन्दोलन प्रगति की ओर है उनकी सोच अनुसार सहकारिता में शिक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए गुजरात के जन जन के सहकारी नेता सहकारिता में त्याग की भावना से काम करने वाले त्रिभुवनदास जी के नाम से सहकारी यूनिवर्सिटी का गठन किया गया है जिसमें सहकारिता क्षेत्र में प्रवेश के माध्यम से योजनाओं में डिप्लोमा स्नातक, स्नातोत्तर एवं पी. एच. डी. की डिग्री रहेगी, जिससे युवा वर्ग सहकारिता मे एक नया व्यवसाय के माध्यम से जुड़ेंगे। तेजसिंह ठाकुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कहा गया की सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में सहकारी सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके अन्तर्गत गत वर्ष की कार्ययोजना एवं आगामी वर्ष की कार्ययोजनाओं पर विचार विमर्श किया जाता है।

किसानों की आय वृद्धि हेतु इंदौर में एफपीओ एवं एफएफपीओ प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

इंदौर। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा इंदौर में एफपीओ (कृषक उत्पादक संगठन) एवं एफएफपीओ के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एफपीओ/एफएफपीओ के प्रतिनिधियों को व्यवसाय संवर्धन, आय वृद्धि तथा संस्थाओं के सतत एवं प्रभावी संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान करना रहा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त सहकारिता श्री मनोज जायसवाल रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की क्षेत्रीय निदेशक सुश्री इंद्रजीत कौर, उप निदेशक श्री गौरव कुमार शाक्य, उप संचालक (उद्यानिकी) श्री त्रिलोक चंद वास्कले, भूमिशा ऑर्गेनिक्स की श्रीमती प्रतिभा तिवारी, डिक्की के अध्यक्ष श्री अनिल सरवैया तथा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ की ओर से डोमेन एक्सपर्ट श्री संतोष येडे, डॉ. योगेश नामदेव, श्री रॉबिन सक्सेना एवं श्री सुभाष नंद तिवारी ने कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए एफपीओ गठन, प्रबंधन, वित्तीय सुदृढ़ता, व्यवसाय विकास, योजनाओं का लाभ, तथा जमीनी स्तर पर आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों एवं उनके समाधान विषयों पर अपने-अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम के दौरान श्री अनिल सरवैया ने एफपीओ एवं एफएफपीओ के प्रतिनिधियों को व्यवसाय से जुड़ाव, आय वृद्धि तथा संस्थाओं के सतत संचालन के व्यावहारिक पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। श्रीमती प्रतिभा तिवारी ने जैविक उत्पादों एवं मूल्य संवर्धन के अवसरों पर प्रकाश डाला।

वहीं सुश्री इंद्रजीत कौर, क्षेत्रीय निदेशक, एनसीडीसी भोपाल ने एफपीओ प्रतिनिधियों को नए सदस्य जोड़ने, व्यवसाय विस्तार करने एवं नए व्यवसाय प्रारंभ करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी तथा भारत सरकार की 10,000 एफपीओ गठन योजना की उपयोगिता पर प्रकाश डाला।श्री मनोज जायसवाल, उपायुक्त सहकारिता ने अपने संबोधन में कहा कि एफपीओ किसानों की आय बढ़ाने, बाजार से सीधे जुड़ने तथा आत्मनिर्भर बनने का सशक्त माध्यम हैं और इनके सफल संचालन में प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम का संचालन एनसीडीसी के श्री गौरव जादौन द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एफपीओ के सीईओ, लेखाधिकारी, बोर्ड सदस्य एवं अन्य प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता की तथा सभी वक्ताओं के व्याख्यानों को अत्यंत उपयोगी, ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी बताया।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर द्वारा आयोजित 15 दिवसीय अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम-2025 व्यवहारिक अध्ययन भ्रमण सम्पन्न

इंदौर, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर द्वारा संचालित15 दिवसीय अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम – 2025के अंतर्गत प्रशिक्षु प्रतिभागियों काव्यवहारिक अध्ययन भ्रमण सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस भ्रमण का उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों को कक्षा में प्राप्त सहकारिता एवं प्रबंधन संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हुए वास्तविक कार्यप्रणाली का अनुभव कराना था। अध्ययन भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों ने निम्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया -

- कृषि एवं ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली
- प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) की संचालन प्रणाली
- एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) के व्यवसाय मॉडल
- डेयरी एवं प्रसंस्करण सहकारी संस्थाओं की उत्पादन एवं विपणन प्रक्रिया
- लेखा, वित्तीय प्रबंधन एवं ई-गवर्नेन्स प्रथाओं काअवलोकन

भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने प्रशिक्षणार्थियों को संस्थाओं के संचालन, सदस्यता प्रबंधन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन तथा सहकारिता के आधुनिक स्वरूप पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रतिभागियों ने भी अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु सक्रिय रूप से चर्चा की।

(पृष्ठ 1 का शेष)

सहकारी संस्थाएं किसानों को सशक्त....

- किसानों से पूसा बासमती धान क्रय करने के लिए किसानों का आर्थिक लाभ सुविधा सुनिश्चित करते हुए मैजिस्टिक प्रायवेट लिमिटेड से अनुबंध किया गया है।
- पराली की समस्या के निराकरण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।
- बीज संघ द्वारा बीज व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए एमपी चीता ब्रांड लांच किया गया है।
- नवीन एम पैक्स, डेयरी सहकारी समिति और मत्स्य सहकारी समिति के तहत कुल 1,601 समितियों का गठन।
- मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अभिनव पहल CPPP के तहत 19 एम.ओ.यू का निष्पादन।
- कंपनियों से 10,000 से अधिक विस्थापित लोगों की 350 सहकारी समितियां गठित कराकर विस्थापितों को सुरक्षा गार्ड, माली, श्रमिक जैसे कार्यों के लिये रोजगार दिया गया।

आगामी तीन वर्षों की कार्य योजना

- पैक्स के डिफॉल्टर किसानों को मुख्य धारा में लाया जाएगा।
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पैमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ग्राहकों को क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध कराना।
- समस्त जिला बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग (व्यू फैसिलिटी) की सुविधा।
- सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास के लिए कौशल इको सिस्टम को विस्तार दिया जाएगा।

प्रमुख बिन्दु

- किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना सहकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य।
- वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
- किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने और फसल चक्र के अनुसार उन्हें सुगमता से सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग कृषि विपणन सहकारी समितियां को मजबूत बनाने बनाने पर विशेष ध्यान दे।
- सहकारी समितियों का प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटराईजेशन किया जाए।
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पंचायत स्तर पर पैक्स स्थापित किए जाएं।
- सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग ने अपेक्स बैंक की 4 करोड़ 27 लाख 4 हजार 190 रुपए अंश पूंजी का लाभांश चेक भेंट किया।

नि:शुल्क टूल-किट वितरण आयोजन

नौगांव। सहकारिता एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल तथा कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव में सीएचसीडीएस योजना अंतर्गत नि:शुल्क टूल-किट वितरण कार्यक्रमका सफल आयोजन किया गया।कार्यक्रम में 30 महिला प्रशिक्षार्थियों को हस्तशिल्प आधारित टूल-किट वितरित की गईं, जिससे वे प्रशिक्षण उपरांत अपने कौशल को स्वरोजगार एवं समूह-आधारित रोजगार में परिवर्तित कर सकें। मुख्य अतिथि श्री अर्चित सहारे, सहायक निदेशक, कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), ग्वालियर ने सीएचसीडीएस योजना की उद्देश्यपरकता, पात्रता मानदंड, कौशल उन्नयन के अवसर तथा विपणन एवं ब्रांडिंग से संबद्ध विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम का संचालन श्री हृदेश कुमार, जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव द्वारा किया गया। उन्होंने सहकारी संघ भोपाल द्वारा संचालित प्रशिक्षण गतिविधियों एवं महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु चल रही पहल की जानकारी दी। कार्यक्रम में शीड संस्था, भोपाल से श्री मनीष राजपूत, श्री अवतार सिंह राजपूत, मास्टर ट्रेनर सुश्री हुमैरा खान तथा डिज़ाइनर सुश्री अर्चना सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव के जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री खूबचंद नाई एवं केंद्र का समस्त स्टाफ कार्यक्रम में सक्रिय रूप से मौजूद रहा।

(पृष्ठ 1 का शेष)

मार्च 2026 तक सभी पैक्स को ई-पैक्स ....

किसानों की आर्थिक उन्नति के लिये यह सबसे प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल संस्थागत व्यवस्था नहीं, बल्कि यह सामूहिक प्रगति और साझी जिम्मेदारी की भावना पर आधारित एक व्यापक आर्थिक मॉडल है। राज्य सरकार सहकारिता तंत्र को अधिक मजबूत, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने के लिये निरंतर कार्य कर रही है।

पैक्स अब बनेंगी बहुउद्देशीय संस्थाएँ

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बदलते कृषि परिवेश में पैक्स का दायरा तेजी से बढ़ा है। अब पैक्स केवल ऋण वितरण, खाद-बीज उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वे बहुउद्देशीय सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली ग्रामीण संस्थाएँ बन रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक राज्य की सभी पैक्स को आधुनिक 'ई-पैक्स' के रूप में परिवर्तित कर डिजिटल संचालन से जोड़ें।

सीपीपीपी मॉडल से आएंगे दूरगामी परिणाम

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारिता ढाँचे में सुधार के लिये सीपीपीपी (Cooperative–Private–Public Partnership) मॉडल की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि "यह मॉडल सहकारिता संस्थाओं को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हुए उन्हें आधुनिक तकनीक, प्रबंधन कौशल और पूँजी निवेश से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बनेगा। आने वाले वर्षों में इसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट:विकास के दो मजबूत पहिये

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति के लिये कॉर्पोरेट और कोऑपरेटिव दोनों ही आवश्यक हैं। दोनों मॉडल एक-दूसरे के पूरक हैं और राष्ट्र के विकास रथ के दो पहिये हैं। सरकार ऐसी नीतियों पर काम कर रही है जिससे सहकारिता संस्थाएँ आत्मनिर्भर, उत्पादक और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। उन्होंने बताया कि कमजोर जिला सहकारी बैंकों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिये राज्य सरकार ने 2027 तक का विशेष लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत पूँजी वृद्धि, प्रबंधन सुधार, कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण और ग्राहक सेवाओं में पारदर्शिता जैसे सभी आयामों पर कार्य किया जा रहा है।

किसानों को समृद्ध बनाने के लिये पशुपालन व दुग्ध उत्पादन पर जोर

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कृषि के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियों को जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। सहकारिता के माध्यम से हम किसानों को मूल्यवर्धन, प्रोसेसिंग, मार्केट लिंक और बेहतर आय के अवसर उपलब्ध कराएँगे। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम में प्रमाण पत्र वितरण- सहकारिता की योजनाओं पर छात्राओं को दी गई विशेष जानकारी

जबलपुर। जबलपुर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर परमाता गुजरी महिला महाविद्यालय (ऑटोनॉमस) जबलपुर की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. रत्ना वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं एवं उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं कोप्रमाण पत्र वितरित किए।

समारोह में जबलपुर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों और वर्तमान योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सहकारिता देश की ग्रामीण व कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की सबसे प्रभावी प्रणाली है।

सहकारिता एवं सहकारी योजनाओं पर दी गई प्रमुख जानकारी

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख सहकारी योजनाओं, सहकारी समितियों की भूमिका और सहकारिता के भविष्य से अवगत कराया गया।

प्रधानमंत्री 'सहकार से समृद्धि' योजना (PM-SAS)

प्राचार्य ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देशभर में नए बहुउद्देशीय PACS की स्थापना, समितियों का उन्नयन तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। PACS को डेयरी, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, FPO, CHC मॉडल, गोडाउन और डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

NCDC की योजनाएँ

छात्राओं को नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) द्वारा संचालित डेयरी, मत्स्य, लैम्प्स, हस्तशिल्प, महिला सहकारी समितियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी गई।

डेयरी सहकार योजना

50,000 करोड़ रुपये की इस राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, प्रोसेसिंग यूनिट, फीड निर्माण, चिलिंग प्लांट और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। छात्राओं को बताया गया कि महिलाओं के लिए डेयरी सहकारी समितियों में रोजगार व उद्यम के बड़े अवसर उपलब्ध हैं।

PACS का उन्नयन एवं डिजिटलीकरण

मेगा डिजिटल कोऑपरेटिव मिशन के तहत PACS को कम्प्यूटरीकृत, बहुउद्देशीय एवं आधुनिक बनाया जा रहा है। इन समितियों के माध्यम से फसल ऋण, उर्वरक वितरण, MSP खरीद, CSC सेवाएँ तथा ऑनलाइन भुगतान की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मध्यप्रदेश में FPO विकास

कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि राज्य में CBBO मॉडल के अंतर्गत बड़ी संख्या में किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाए जा रहे हैं, जहाँ कृषि व्यवसाय, विपणन, वित्तीय प्रबंधन और उद्यमिता के अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

छात्राओं के लिए सहकारिता क्षेत्र में अवसर

मुख्य अतिथि डॉ. वर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि सहकारिता के माध्यम से युवाओं, विशेषकर छात्राओं के लिए- • प्रबंधन, • लेखांकन, • सामाजिक अनुसंधान, • डेयरी एवं कृषि उद्यम, • स्टार्टअप तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में करियर एवं उद्यमिता के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने सहकारिता के महत्व, इसके आर्थिक व सामाजिक योगदान तथा स्वरोजगार के अवसरों की सराहना की।

इंटर्नशिप के माध्यम से महिला सशक्तिकरण : सहकारिता विभाग की पहल से छात्राएँ हुईं लाभान्वित

नौगांव। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारिता विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा युवाओं को सहकारिता से जोड़ने हेतु सहकारिता इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव में शासकीय बापू डिग्री कॉलेज, नौगांव की 27 छात्राओं के लिए15 दिवसीय अल्पकालिक इंटर्नशिप का आयोजन दिनांक 18 नवम्बर से 02 दिसंबर 2025 तक किया गया।

इंटर्नशिप के प्रमुख विषय

इंटर्नशिप के दौरान छात्राओं को सहकारिता से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया गया, जिनमें—

- सहकारिता की मूल अवधारणा
- सहकारी संस्थाओं के प्रकार एवं उनकी कार्यप्रणाली
- सहकारी लेखा एवं ऑडिट
- सहकारी संस्थाओं की पंजीयन प्रक्रिया
- प्रशिक्षण देने की कला (Training Skills)

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक छात्रा को एक विद्यालय में जाकर"सहकारिता एवं रोजगार के अवसर"विषय पर युवाओं को प्रशिक्षण देने का प्रायोगिक कार्य कराया गया, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता एवं व्यवहारिक दक्षता का विकास हुआ।

समापन समारोह

कार्यक्रम का समापन शासकीय बापू डिग्री कॉलेज, नौगांव के प्राचार्य डॉ. पी.के. मिश्राद्वारा छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित कर किया गया।

डॉ. मिश्रा ने इस महत्वपूर्ण पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण भविष्य में युवाओं को सहकारिता क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायक सिद्ध होंगे।

कॉलेज के प्रो.डॉ. एच. सी. नायक ने कॉलेज में संचालित विभिन्नस्किल डेवलेपमेंट कार्यक्रमों की जानकारी साझा की।

केंद्र द्वारा मार्गदर्शन एवं सहयोग

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव के प्राचार्यश्री शिरीष पुरोहितने इंटर्नशिप के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षकश्री हृदेश रॉयद्वारा किया गया।

प्रशिक्षक श्री बाबूलाल कुशवाहा एवं लिपिक श्री खूबचंद सेन का कार्यक्रम आयोजन में सहयोग सराहनीय रहा।

HDCM प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न - 32 सहकारी निरीक्षकों ने हासिल की समग्र प्रशासनिक, तकनीकी एवं व्यवहारिक दक्षता

भोपाल। सहकारिता विभाग के लिए सशक्त एवं दक्ष मानवबल तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल में आयोजित हायर डिप्लोमा इन को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट (HDCM) का 20-सप्ताहीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कुल 32 नव-नियुक्त सहकारी निरीक्षकोंने यह व्यापक प्रशिक्षण पूर्ण कर सहकारिता व्यवस्था में ज़मीनी और प्रशासनिक कार्यों की गहन समझ विकसित की।

21 जुलाई से 08 दिसंबर 2025 तक चला विस्तृत आवासीय प्रशिक्षण

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारिता क्षेत्र में विकसित हो रही नई चुनौतियों और तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। कार्यक्रम का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन, महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह, एवं सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य श्री जी.पी. मांझी के मार्गदर्शन में किया गया। पूर्व प्राचार्य श्री अरुण कुमार जोशीकी विशेष सहभागिता से प्रशिक्षण की गुणवत्ता और अधिक सुदृढ़ हुई।

कढ़ाई हस्तशिल्प टूल-किट वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल तथा कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सीएचसीडीएस योजना अंतर्गत कढ़ाई आधारित निशुल्क टूल-किट वितरण कार्यक्रमका सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 120 महिला प्रशिक्षार्थियोंको कढ़ाई एवं हस्तशिल्प कार्य हेतु उन्नत टूल-किट प्रदान की गईं, ताकि वे कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम स्थापना की दिशा में सशक्त बन सकें।

मुख्य अतिथि श्रीनर सिंह सैनी, सहायक निदेशक, कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भोपाल रहे। विशिष्ट अतिथियों में श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल; श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल; तथा श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ संस्था से श्री धर्मेंद्र सिंह राजपूत तथा कार्यक्रम में संघ से श्री संतोष येड़े, श्री सुभाष नंद तिवारी, श्रीमति श्रद्धा श्रीवास्तव, श्री धनराज सैंदाणे भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्होंने कढ़ाई कला के तकनीकी पहलुओं एवं बाज़ार संभावनाओं पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया।

मुख्य अतिथि श्री नर सिंह सैनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हस्तशिल्प आधारित कौशल प्रशिक्षण योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रही हैं।

श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, ने अपने उद्बोधन में कहा कि सहकारी संघ का लक्ष्य ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि संघ द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे प्रशिक्षण एवं आजीविका कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है, जिससे हजारों महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों से आग्रह किया कि वे प्राप्त प्रशिक्षण एवं टूल-किट का उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करें और बाजार से सीधा जुड़ाव स्थापित करें।महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि सहकारी संघ द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।प्राचार्य श्री गणेश प्रसाद मांझी ने प्रशिक्षण केंद्र की गतिविधियों एवं उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रशिक्षार्थियों को निरंतर अभ्यास और नवाचार के लिए प्रेरित किया।

सहकारी सम्मेलन का सफल आयोजन : सहकारिता को जन-आंदोलन का रूप देने का संकल्प

सीहोर। जिला सहकारी संघ मर्यादित, सीहोर एवं इफको के संयुक्त तत्वावधान में बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्यादित, निपानियाकलॉ में सहकारी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुधीर कैथवास, उपायुक्त सहकारिता ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में मनोज शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीहोर उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में एस.के. सक्सेना (अंकेक्षण अधिकारी), विजय कुमार द्विवेदी (रिजनल मैनेजर, इफको), भारत सिंह (पर्यवेक्षक), एम.डी. दीपक चन्द्रवंशी, जनपद सदस्य देवेन्द्र चन्द्रवंशी एवं विभिन्न ग्रामों के सरपंच — नरेश वंशकार (निपानिया), महेश वर्मा (लोंदिया), राजेश वर्मा (धनखेड़ी), नरेश गौर (शेखपुरा), आज़ाद मेवाड़ा (देवली) तथा आनंद कुमार (रोला) शामिल हुए।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा इफको एमसी के कृषि रसायन बिक्री केंद्र का फीता काटकर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत समिति प्रबंधक महेन्द्र चौधरी एवं सुरेश गौर द्वारा साफा बांधकर तथा पुष्पमालाओं से किया गया।

इफको के रिजनल मैनेजर विजय कुमार द्विवेदी ने कृषि रसायनों के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इफको किसानों के लिए कृषि रसायनों के उपयोग पर आधारित विशेष बीमा योजना भी संचालित कर रहा है, जिससे किसानों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है।

उपायुक्त सहकारिता सुधीर कैथवास ने कहा कि वर्ष 2025 को भारतअंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्षके रूप में मना रहा है। इस अवसर पर सहकारी संस्थाओं को मजबूत करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को सहकारिता से जोड़कर आत्मनिर्भर रोजगार उपलब्ध करवाना लक्ष्य है। सहकारी योजनाओं

को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जिला सहकारी संघ द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज शर्मा ने अपने उद्बोधन में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के अंतर्गत इफको भी सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले कृषि रसायन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि मोगराराम एवं निपानिया में बिक्री केंद्र संचालित हैं, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है। यह हमारे प्रधानमंत्री एवं सहकारिता मंत्री की दूरदृष्टि का परिणाम है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा सहकारिता मंत्री कैलाश विश्वास सारंग की कार्ययोजना के अनुरूप सहकारिता को एक जन-आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिससे किसानों एवं बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके।

कार्यक्रम का संचालन देवेन्द्र चन्द्रवंशी, सुनील सक्सेना, तेजसिंह ठाकुर एवं ओमप्रकाश ने किया। अंत में आभार बहुउद्देशीय संस्था निपानिया के प्रबंधक श्री सुरेश गौर ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।